

बारह राज्यों में सार्वजनिक शौचालयों में सुधार के लिए आईटीआई के फीडबैक डिवाइस और ऑनलाइन डैशबोर्ड सेवाएं ।

शहर के स्वच्छता के अनुभव को बेहतर बनाने और पूरे देश में सार्वजनिक शौचालयों में खराब स्वच्छता के अनुभव से निपटने के प्रयास में, आईटीआई लिमिटेड, भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई और दूरसंचार उपकरणों के निर्माण में अग्रणी, ने स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित प्राधिकरणों को सार्वजनिक शौचालयों से वास्तविक समय का फीडबैक डेटा प्रदान करने हेतु आज वेबसाइट www.itilt-dswacchththafeedback.co.in को लॉन्च किया है ।

वेबसाइट आईसीटी के सक्षम डैशबोर्ड में 'स्वच्छता फीडबैक प्रणाली' है, जो भारत के बारह राज्य सरकारों में स्थापित सभी फीडबैक डिवाइसों से ऑखों-देखी डेटा प्रदान करती है, जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पांडिचेरी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा । यह वेबसाइट आईटीआई लिमिटेड के देखरेख एवं स्वामित्व में है । बाकी के कमरे में स्थापित डिवाइस (उपकरणों) से जीपीआरएस के माध्यम से प्राप्त किए गए फीडबैक डेटा और क्लाउड सर्वर में संग्रहीत होंगे और सभी राज्यवार जानकारी को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा ।

अब तक, आईटीआई ने 5 राज्यों में - दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और तेलंगाना के नगर निगमों में लगभग 300 उपकरण स्थापित कर चुकी हैं । कर्नाटक में, आईटीआई ने पहले ही भारत के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बृहत् बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के 600 स्थानों में से 100 फीडबैक डिवाइस स्थापित कर चुकी हैं । सुसज्जित सार्वजनिक शौचालय, नागरिकों को सीधे शौचालयों की जगहों से राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों को प्रतिक्रिया देने में सक्षम होगा ।

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के तहत स्वच्छ भारत का सपना साकार करने के लिए, शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) ने शौचालयों की सफाई के लिए नियमित रूप से निगरानी करने के लिए सार्वजनिक शौचालयों पर प्रतिक्रिया उपकरणों को स्थापित करने की योजना बनाई थी । इसे देखते हुए, एमओयूडी ने अप्रैल, 2017 में आईटीआई लिमिटेड से फीडबैक उपकरणों की खरीद पर विचार करने के लिए बारह राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए थे ।

स्वच्छता फीडबैक वेबसाइट की शुरुआत करते हुए आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एस गोपु ने कहा, "स्वच्छभारत मिशन के अंतर्गत, आईटीआई शहरी विकास मंत्रालय (एमओडी) के साथ मिलकर सार्वजनिक शौचालयों पर प्रतिक्रिया उपकरणों को स्थापित करेगी ताकि नगर निगम निकायों के समर्थन के साथ 12 राज्यों के जिलों में नियमित रूप से शौचालयों की स्वच्छता की निगरानी और रखरखाव हो सके । एमओयूडी का प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के सरकार के दृष्टिकोण से पूरक है, जहां आईटीआई प्रोटोटाइप निर्माण में स्टार्टअप की मदद कर रहा है और बाजार में प्रवेश करने के लिए मददगार साबित हो रहा है। स्वच्छता फीडबैक वेबसाइट, आईटीआई लिमिटेड की प्रमुख पहलों में से एक है जो संबंधित

अधिकारियों को पूरे इलाकों में सार्वजनिक शौचालयों से वास्तविक समय की प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाती है ।"

अधिकृत अधिकारी एमओयूडी, एसबीएम, महानगर निगम और आईटीआई लिमिटेड, स्थापित उपकरणों से प्राप्त वेबसाइट पर वास्तविक समय डेटा का उपयोग कर सकते हैं । यह वेबसाइट संबंधित 12 राज्यों में सार्वजनिक शौचालयों के स्थानों को देखने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी सक्षम करेगी । फीडबैक डेटा की एक विश्लेषण रिपोर्ट को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आधार पर भी देखा जा सकता है । इसके पश्चात् वेबसाइट, शौचालय लोकेटर फीचर द्वारा समर्थित होगी ताकि शहर में रहने वाले लोग आसानी से इसका पता लगा सके ।

सार्वजनिक शौचालयों के फीडबैक डिवाइस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आईटीआई लिमिटेड के निदेशक, उत्पादन और विपणन, श्री के. अलागेसन ने कहा, "यूनियन शहरी विकास मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद, हमने प्रत्येक सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में उपकरणों की स्थापना शुरू कर दी है । कुछ महीनों के अंदर स्थापना का काम पूरा हो जाएगा । इससे हमें नागरिकों को बेहतर नागरिक सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी ।"

डिवाइस के फीडबैक बटन में शौचालयों के बारे में अच्छी, औसत और खराब जैसी स्वच्छता की जानकारी है । अगर प्रतिक्रिया किसी विशेष स्थान से 'खराब' की अधिक है, तो डिवाइस आवश्यक कार्रवाई के लिए प्राधिकरण को एक एसएमएस अलर्ट भेज देगा । प्रथम स्तर पर, वृद्धि मैट्रिक्स संबंधित नगरपालिका द्वारा तय किया जाएगा । यदि कार्रवाई में देरी या कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो अगला मुद्दा अगले स्तर के अधिकारियों के पास भेजा जाएगा । इसके अलावा, जब तक उक्त समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक मुद्दा उच्च अधिकारियों तक बढ़ाया जाएगा । दैनिक रिपोर्ट प्रत्येक स्थान के लिए प्रत्येक दिन 8:00 बजे स्वचालित रूप से जेनरेट हो जाएगी और संबंधित प्राधिकरणों को ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी ।